

उत्तराखण्ड शासन

आवास अनुभाग-2

संख्या-2008/V/आ0-2014-127(आ0)/2013,

दिनांक 07 फरवरी, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-152/9-आ0-1-1998, दिनांक 15 जनवरी, 1998(उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) द्वारा आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड की स्थापना उक्त खाते में विभिन्न स्रोतों से अर्जित प्राप्तियों को जमा कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-5 घ में यह व्यवस्था निर्धारित है कि अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमन शुल्क का 50 प्रतिशत अंश आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते में तथा शेष 50 प्रतिशत विकास प्राधिकरण का अंश होगा।

3- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15, जनवरी, 1998 के प्रस्तर- 5 घ में उल्लिखित व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 01-4-2013 से यह व्यवस्था निर्धारित की जाती है कि अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमन शुल्क का न्यूनतम 75 प्रतिशत अंश तथा अधिकतम 90 प्रतिशत तक आवासीय इन्फ्रास्ट्रक्चर खाते में इस प्रतिबन्ध के साथ जमा किया जायेगा कि 75 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत के सीमान्तर्गत अवस्थापना मद में धनराशि का हस्तान्तरण, प्राधिकरण बोर्ड की सहमति के उपरान्त, प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जाए तथा शेष न्यूनतम 10 प्रतिशत एवं अधिकतम 25 प्रतिशत यथास्थिति विकास प्राधिकरण के अंश के रूप में जमा किया जायेगा।

4- उक्त के अतिरिक्त उक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-152/9-आ0-1-1998, दिनांक 15 जनवरी, 1998 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2008/V/आ0-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, कैम्प कार्यालय-देहरादून/नैनीताल।
- 2- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार।
- 5- सम्बन्धित नगर पालिका परिषद, उत्तराखण्ड।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(डॉ0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव।